वाले गणेश, प्रगति, दीनबन्धु और प्लांट नामक चार सस्ते माडलों का अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही विकास हो चुका है तथा इनका विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा बहु-पोशी डिजाइनों के विकास तथा गैस उत्पादन की कुशलता को बढ़ाने के लिए बम्बई, कालीकट, हैदराबाद, जोरहाट, पटना, पांडिचेरी, पुणे तथा सांगली में अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

Second Mine Expansion of Neyveli Lignite Corporation Limited

2368. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the spreaders project of the second mine expansion of Neyveli Lignite Corporation Limited has got delayed due to inexperienced handling by WMI (Cranes) Limited, Bombay and its foreign collaborator M/s. MANGHH of West Germany;

(b) whether the technical consultant of the project the Rheinbraun Consulting of West Germany has also made adverse observations against the said combine;

(c) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereto;

(d) what are the other reasons for the delay; and

(e) what further steps are being taken to expedite the said project?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

(e) The progress of work is as per the agreed time schedule.

हाथी समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

2369. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के संबंध में हाथी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का किस हद तक क्रियान्वयन किया जा रहा है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केवल जेनेरिक नामों वाली औषधियों ही बेची जायें, क्या व्यवस्था की गई है?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औषधी नीति, 1978 की घोषणा हाथी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी। दिसम्बर, 1986 में घोषित नये उपायों का उद्देश्य अंतरालों को पाटना तथा 1978 की नीति के कार्यान्वयन में देखी गई अपर्याप्त ताओं को ठीक करना है।

(ख) 1986 के नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक जेनेरिक नामों को व्यापार नाम के दुगने आकार में प्रदर्शित किया जायेगा। आवश्यक औषधों की सूची में शामिल सभी औषधों के मामले में धीरे-धीरे जेनेरिक नामों को अपनाया जायेगा।

बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिए योजनाएं

2370. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बिहार में बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए अपनी योजनाओं में कौन-कौन से

कार्यक्रम शामिल किये हैं और ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं जो आरम्भ कर दी गयी हैं तथा पूरी होने वाली है ; और

(ख) कहलगांव में बिजली का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ौतरी करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिनसे 7वीं तथा 8वीं योजना की बाकी अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होंगे :—

स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	के दौरान लाभ (मेगावाट)	
		1987-90	8वीं योजना
1. उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना	24.0	24.0	–
2. सोन पश्चिमी सम्पर्क जल विद्युत परियोजना	6.6	6.6	–
3. सोन पूर्वी सम्पर्क जल-विद्युत परियोजना	3.3	3.3	–
4. पूर्वी गंडक नहर (जल विद्युत)	15.0	15.0	-
5. चंदेल जल-विद्युत परियोजना	8.0	–	8.0
6. तेनघाट ताप विद्युत परियोजना	420.0	210.0	210.0
जोड़ :	476.9	258.9	218.0

इसके अतिरिक्त, पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं और चूखा परियोजना से भी राज्य को इसका हिस्सा प्राप्त होगा। पतरातू, बरौनी और कारवी धैया ताप-विद्युत केन्द्रों में 67.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 25.81 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

(ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक के पहले यूनिट को 1991 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है ?

उत्तर प्रदेश की बिजली सम्बन्धी मांग

2371. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस वर्ष के सूखे की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की मांग को किस प्रकार पूरा करनेमें का विचार रखती है ;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता है और यहां बिजली की मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है ; और

(ग) कृषि, औद्योगिक और गैर-सरकारी क्षेत्र को अलग-अलग बिजली सप्लाई में कितने प्रतिशत कटौती वहन करनी पड़ेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इस वर्ष सूखे की स्थिति के दौरान जहां तक संभव हो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से विभिन्न उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया था। इन उपायों में ये शामिल हैं, तापविद्युत केन्द्रों से विद्युत का अधिक उत्पादन करना, भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को